Agro-Service Centres in North Eastern States

*879. SHRI S. N. SINGH DEO: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the scheme of Agro-Service centres is being implemented throughout the country but there has been no encouraging response from the North Eastern States;

(b) if so, the reasons for this non-encouraging response from these States, State-wise;

(c) the advice given to the States; and

(d) action taken by the States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) (a) Yes Sir.

(b) and (d) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha

(c) States are being advised to give wide publicity outlining the broad features of the Scheme through press, educational Institutions and employment Exchanges

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के लिए मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण दिया जाना ।

883. श्री हुक्म चन्द कछवाय : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में और अधिक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को कितना ऋण दिया; और

(ख) इस समय कौन-कौन सी योजनाएं विचाराधीन है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) राज्य सरकारों को राज्यों की योजना के अन्तर्गत स्कीमो के लिए सारी वार्षिक योजना के लिए एक-मुश्त ऋण और अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह सहायता किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रो के लिए अलग-अलग योजनाओं या कार्यक्रम के लिए नहीं होती है। तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत आदिवासी विकास के एक विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासियो का आर्थिक विकास तेजी से करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश में बस्तर जिले की दानेवाडा और कोटा तहसील मे लघु सिंचाई की दो आदिवासी विकास एजेंसी परियोजनाएं हाथ मे ली गई है। इन परियोजनाओं में लघु सिंचाई का विकास भी शामिल है इन परियोजनाओ के अन्तर्गत लघु सिंचाई सहित आर्थिक विकास कार्यक्रम के लिए दो वर्ष में अनुदान के रूप में 100 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

पाचवी योजना के शुरू मे की गई समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक विकास के लिए 1974-75 मे मध्य प्रदेश को 57 लाख रुपये की विशेष सहायता उपलब्ध की गई थी, जिसमे लघु सिंचाई भी शामिल है।

(ख) यह राज्य पाचवी योजना के दौरान आदिवासी विकास के लिए योजना आयोग के परामर्श से उप-योजनायें बना रहे है।

Steps for Production of Cashew

*885. SHRIMATI BHARGAVI THANKAPPAN: Will the Minister of AGRICULTURE & IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether cultivation of cashew widely grown in Kerala, Tamil Nadu and Karnataka has been found to be very successful in other parts of the